THE CORE

INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING

PIB HINDI

FEBUARY MONTH

WWW.THECOREIAS.COM

+91-8800141518

INDEX (तालिका)

PRELIMS (प्रारंभिक)	MAINS (मुख्य परीक्षा)
.1.कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट को आज जारी किया गया	1.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय-
2.शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ	2.'नो माई इंडिया' कार्यक्रम
3.अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम,2019	3.राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम पुणे में आयोजित
4.राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना	4.ओडिशा में 12वां क्षेत्रीय मानक सम्मेलन
5.जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना	5.आपदा जोखिम प्रबंधन पर इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन की बैठक
6. डीडी अरुणप्रभा	6.महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने के लिए नियम अधिसूचित किए
7.अक्षय पात्र फाउंडेशन	7.नदी सूचना प्रणाली-आरआईएस (फरक्का-पटना)
8.संचार उपग्रह जीसैट-31	8.राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति -2019
9.जीईएम और सीसीआई	9.विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव
10.स्वास्थ्य और शिक्षा' 15वें वित्त आयोग की विशेष थीम होगी	10.किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का शुभारंभ
11.ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP)	11.डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप से जुड़ी पहलों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण लांच
12.राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी)	12.मेगा फूड पार्क
13.डीलर स्वामित्व डीलर परिचालित (डीओडीओ) मॉडल का शुभारम्भ	13.पुलिस सेवाओं का 'ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे'
14.क्रेडाई कन्फेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) यूथकॉन-19	14.'शिष्ट भारत अभियान'
15.'आउटरीच' कार्यक्रम	15.ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरूआत की
16.राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति	16.दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा
17.प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना	17.सिधुं नदी जल संधि 1960 : भारत में वर्तमान स्थिति
18."टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन" पर राष्ट्रीय सम्मेलन	18.राष्ट्रीय युद्ध स्मारक
19.अमृत शहरों- रायगढ़, अंबिकापुर और कुंभकोणम के नगर निगमों को मिले शीर्ष स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार	19.बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रतिस्पर्धा 'आईप्रिज्म'
20.केरल में 'इको सर्किट: पठनमथिट्टा-गवी-वागामोन-थेक्कडी'	20.सीआईआई और आईआईसीए के बारे में
	21. इंडिया -कोरिया
	22. 'दिल्ली घोषणा'
	23.राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019
	24.नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक

THE CORE IAS

21.राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार
22.पीआईएसए (पीसा)
23.अनियमित जमा योजना अध्यादेश, 2019 पर प्रतिबंध की घोषणा
24.स्वदेश दर्शन योजना
25.' राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना '
26.अरूणाचल प्रदेश में सेला टनल
27.मथुरा जिले में मेगा फूड पार्क की आधारशिला

28.अटल नवाचार मिशन
29.स्वच्छ गंगा कोष
30."वन धन योजना"
31.आईएसएल शब्दकोश
32.'सतत'योजना
33.अप्रेंटिसशिप एवं कौशल (श्रेयस) योजना
34.फेम इंडिया योजना दूसरे चरण
35.प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना
36.गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान की आधारशिला
37.टेक-सोप' 2019

THE CORE IAS
THE CORE IAS
THE CORE IAS
India's First Institute Dedicated to Answer Writing
Answer Writing & Test Series for UPSC / UPPCS / BPSC & Other States
GENERAL STUDIES
X1, X2, X3, X4, Batches
OPTIONAL
- Philosophy
- Anthropology
- History
- Hindi Literature
- Sanskrit Literature
- Geography
MODULE
- Environment & Ecology
- Ethics With Case Studies
- Essay
- CSAT (Sure Qualifying)
- Social Issue
- Economics
- Governance
- NCERT +
Targeted Current Affairs
Prelim - Cum - Mains
The Hindi Analysis
(Editional)
Practice 1000+ MCQs in the class
Mode- Online/ Offline
Medium- Hindi/ English
8800141518 (7827209963
Class:- A 40-41, 2nd Floor Ansal Building Mukherjee Nagar Delhi-110009
Office. : Chamber No. 3, IInd floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

PRELIMS SPECIAL

1.कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट को आज जारी किया गया

कुंभ केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक ही नही है, बल्कि यह पूरे विश्व का एक ज्योतिषीय, सांस्कृतिक और खगोलीय आयोजन है। कुंभ को ज्ञान के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है।

2.शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ

- शहरी समृद्धि उत्सव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय मिशन-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के लाभ सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है। यह आयोजन अपनी पहलों को प्रदर्शित करता है तथा सरकार की अन्य योजनाओं तक स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों की पहुंच सुगम बनाता है। देश भर में इसका शुभारंभ इस सप्ताह के आरंभ में किया गया।शहरी समृद्धि उत्सव के पहले दिन देशभर में महिला स्व सहायता समूहों की अगुवाई वाली रैलियों के साथ हुई। ये रैलियां शहरों में रहने वाले गरीब समुदायों में डीएवाई-एनयूएलएम के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। बहुत से राज्यों द्वारा रोजगार मेलों तथा महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया गया.

THE CORE IAS

3.मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम,2019 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओ को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी

- भारत में प्रथम आईएफसीएस की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की गई है। आईएफसीएस द्वारा वर्तमान में भारतीय कार्पोरेट संस्थाओ और वित्तीय संस्थानो द्वारा विदेशो में शाखा और सहायक कंपनी द्वारा वित्तीय केंद्रो में किए जा रहे वित्तीय सेवाओ और लेनदेन के कार्य को करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा। आईएफसीएस द्वारा लंदन और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रो के अनुरूप व्यापार और नियामक वातावरण प्रदान किया जाएगा। इससे भारतीय कार्पोरेट की

वैश्विक वित्त बाजार तक सरलता से पहुंच संभव हो सकेगी। आईएफसीएस से भारत में वित्तीय बाजार के विकास को ओर बल मिलेगा

- वर्तमान में आईएफसीएस में बैंकिग, कैपिटल मार्केट और बीमा क्षेत्र में कई नियामक जैसे रिजर्व बैक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) कार्यरत हैं। आईएफसीएस में निरंतर सक्रिय कार्य के कारण नियामकों के बीच समन्वय की बेहद आवश्यकता है। आईएफसीएस में वर्तमान में नियमन करने वाले में नियमित स्पष्टीकरण और निरंतर संशोधन की आवश्यकता होती है। आईएफसीएस में वित्तीय सेवाओ और उत्पादों के विकास हेतु केंद्रित और समर्पित नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए देश में वित्तीय बाजार भागीदारको को विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिए एकीकृत वित्तीय नियामक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके साथ ही यह व्यापार करने में सुगमता के उद्देश्य से भी आवश्यक था। एकीकृत प्राधिकरण देश में आईएफसीएस के विकास के लिए वैश्विक कार्यप्रणाली के अनुरूप समकालीन आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- आईएफसीएस की नियामक आवश्यकताओ और वित्तीय क्षेत्र में वर्तमान कानूनो के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलो के विभाग ने आईएफसीएस के लिए पृथक एकीकृत नियामक स्थापित करने के लिए मसौदा अधिनियम तैयार किया था। अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं

- **<u>प्राधिकरण का प्रबंधन</u>**
- प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, रिजर्व बैंक, आईआरडीएआई,सेबी और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नामित एक-एक सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य और दो अन्य पूर्णकालिक या पूर्ण या अंशकालिक सदस्य होंगे।

- **<u>प्राधिकरण के कार्य</u>**
- प्राधिकरण वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा आईएफएससी के लिए पहले से अनुमति प्राप्त सभी वित्तीय सेवाओ और उत्पादो का नियमन करेगा। प्राधिकरण इसके साथ ही समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवा और एफआई का नियमन भी करेगा। प्राधिकरण इसके साथ ही केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद और सेवा तथा वित्तीय संस्थान जिन्हें आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती हो की सिफारिश कर सकता है।

- **<u>प्राधिकरण की शक्ति</u>**

- वित्तीय क्षेत्र के संबधित नियामक जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा प्रयोग की जा रही सभी शक्तियां का प्रयोग पूरी तरह से प्राधिकरण द्वारा आईएफएससी में किया जाएगा। इसमें आईएफएससी से संबधित अनुमति प्राप्त वित्तीय उत्पाद,वित्तीय सेवा और एफआई का नियमन सम्मिलित है।

- **<u>प्राधिकरण की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली</u>**
- प्राधिकरण की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली संसद द्वारा बनाए गए संबधित अधिनियमो के अनुरूप होंगी,जो ऐसे वित्तीय उत्पादो,सेवाओ और संस्थानो में परिस्थिति अनुरूप मान्य होगी

- **<u>केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान</u>**
- केंद्र सरकार संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद प्राधिकरण के प्रयोग के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान कर सकती है।

- **<u>विदेशी मुद्रा में लेनदेन</u>**

  - आईएफएससी में वित्तीय सेवा में लेनदेन प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद निर्धारित विदेशी मुद्रा में किया जाएगा ।
- आईएफएससी के लिए एकीकृत वित्तीय नियामक की स्थापना से व्यापार करने में सुगमता के बिंदु से बाजार में भागीदारी करने वालो को विश्व स्तरीय नियामक वातावरण मिलेगा। इससे भारत में आईएफएससी के अग्रिम विकास को ओर गति मिलेगी और विदेशो में वित्तीय केंद्रो में होने वाली वित्तीय सेवाओ ओर लेनदेन को वापिस लाने में सहायता मिलेगी। आईएफएससी में विशेष तौर पर रोजगार सृजन में अहम वृद्धि के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरो में भी वृद्धि होगी।

<u>4.गौवंश के संरक्षण,सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना</u>

- **<u>आयोग का प्रभाव</u>**
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में स्वदेशी गाय सहित गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप देश में पशुधन क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, जिसका लाभ विशेष रूप से महिलाओ और छोटे एवं सीमांत किसानो को मिलेगा।

THE CORE IAS

- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन,पालन, जैविक खाद और बॉयोगैस आदि के क्षेत्र में कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के विभागो और संगठनो तथा पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयो के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- **आयोग की पृष्ठभूमि**
- गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में गाय के संरक्षण हेतु नीतिगत ढांचा और दिशा मिलेगी और इससे गायों के कल्याण के लिए कानूनों का उचित क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुरूप की गई है।

5.जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना

- पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंजूरी दी। इस सर्किट पीठ के अधिकार क्षेत्र में चार जिले दार्जिलिंग,कलिमपोंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार सम्मिलित होंगे।
- यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट की वर्ष 1988 में हुई पूर्णकालिक बैठक के बाद हुए फैसले और 16 जून, 2006 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंजूरी देने के निर्णय के अनुरूप लिया गया है। 30 अगस्त, 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायधीशो के एक दल ने जलपाईगुड़ी में सर्किट पीठ के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा कर आधारभूत ढांचे संबधी प्रगति का आंकलन किया था।

THE CORE IAS

6. डीडी अरुणप्रभा

- **अरुणाचल प्रदेश** की संस्कृति को सुदृढ़ एवं विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के लिए समर्पित 24x7 सैटेलाइट टीवी चैनल डीडी अरुणप्रभा को लॉन्च किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह चैनल राज्य की संस्कृति के दूत के तौर पर काम करेगा और पूरे भारत के लोगों को राज्य की सुंदरता एवं संस्कृति से अवगत कराएगा।

7.अक्षय पात्र फाउंडेशन

- "अक्षय पात्र एक सामाजिक स्टार्ट-अप है, जो एक आंदोलन में बदल गया है और यह स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करता है"। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में

अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा 3 अरबवें भोजन के लिए सेवा के प्रतीक के रूप में पट्टिका का अनावरण करेंगे।

- **'होराई' (असम का एक पारंपरिक ट्रे जिसमें स्टैंड लगा होता है)**

8.संचार उपग्रह जीसैट-31 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च

8.जीईएम और सीसीआई

- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ई-मार्केटप्लेस में निष्पक्ष एवं प्रतियोगी पर्यावरण बनाने के लिए 6 फरवरी, 2019 को एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।**
- सीसीआई और जीईएम दोनों ने विश्लेषण करने के उन्नत उपकरण और व्यावसायिक गुटबाजी जैसी गलत परम्परा की पहचान की प्रक्रिया की अहमियत की प्रशंसा की। सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विरोधी गलत परम्पराओं की पहचान के लिए सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की कुशलता का इस्तेमाल करना है।
- जीईएम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच है। जीईएम ने प्रामाणिक विक्रेताओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया और वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए एक ई-मार्केटप्लेस का निर्माण किया।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, जिसकी पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 लागू करने और प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी है।

9.स्वास्थ्य और शिक्षा' 15वें वित्त आयोग की विशेष थीम होगी

- *बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :-*
- भारत की आबादी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा नियामकीय रूपरेखा का आकलन करना और स्वास्थ्य क्षेत्र का संतुलित एवं त्वरित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए इसकी ताकत एवं कमजोरियों पर गौर करना।
- भारत में वर्तमान वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के उपाय सुझाना और सुपरिभाषित स्वास्थ्य पैमानों पर खरे उतरने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
- अपने स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तौर-तरीकों पर समग्र रूप से गौर करना और अपनी रूपरेखा को इन तौर-तरीकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रयास करना, ताकि अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
- अध्यक्ष ने बैठक में यह घोषणा की कि 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा' 15वें वित्त आयोग की एक विशेष थीम होगी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्त आयोग की एक विशेष थीम होती है। श्री विजय एल. केलकर की अध्यक्षता वाले 13वें वित्त आयोग की विशेष थीम 'जीएसटी का पुनर्गठन' निर्धारित की गई थी।

10.ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP)

THE CORE IAS

- ओएएलपी ने ***HELP की*** सभी विशेषताओं को अपनाया जिसमें कम रॉयल्टी दरें, तेल उपकर, एकसमान लाइसेंसिंग प्रणाली, विपणन और मूल्य स्वतंत्रता, राजस्व साझाकरण मॉडल, पूर्ण अनुबंध जीवन के लिए सभी अनुरक्षित क्षेत्र पर अन्वेषण अधिकार आदि शामिल हैं।

11.राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी)

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी पंजीकृत सोसायटी है। एनपीसी 12 फरवरी को अपना 61वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वर्ष का विषय है – उत्पादकता और स्थिरता के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था। एनपीसी अपने स्थापना दिवस को उत्पादकता दिवस के रूप में मनाती है और यह 12 से 18 फरवरी 2019 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का भी आयोजन कर रही है। इस वर्ष का विषय उपयोग को आवृत्ति बनाने के लिए सर्कुलर व्यापार मॉडल के लिए एक विशिष्ट अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। एक कुशल सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शुरूआत से उद्योग और हितधारक वर्तमान में भी और भविष्य में भी लाभान्वित होंगे।

12.डीलर स्वामित्व डीलर परिचालित (डीओडीओ) मॉडल का शुभारम्भ

13.क्रेडाई कन्फेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) यूथकॉन-19-

- यूथकॉन क्रेडाई का वार्षिक युवा सम्मेलन है, जो भारत में रीयल एस्टेट उद्योग की युवा पीढ़ी को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित किया जाता है।
- क्रेडाई की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। यह भारत के 200 से अधिक शहरों के रीयल एस्टेट डेवलपरों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है।

14.'आउटरीच' कार्यक्रम

- वस्त्र मंत्रालय हितधारकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे स्थानीय बैंकों के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए कैंप लगाना, ई-धागा के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों को उपकरण किट का वितरण, कारीगारों तथा बुनकरों के लिए पहचान-पत्र का पंजीयन व वितरण, 24x7 हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। भारत के कुल वस्त्र उद्योग में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है। नई पहलों से अधिकांश इकाइयों को फायदा मिलेगा जैसे नए ऋणों के लिए ब्याज दर में दो प्रतिशत की कटौती, निर्यात क्रेडिट के

लिए दो प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती, 59 मिनटों के अंदर 1 करोड़ तक के ऋण-स्वीकृति आदि.

15.राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति

❖ वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फैलो डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2017 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के जरिये 14 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

16.प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना

- देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है। पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए नहीं जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

- **न्यूनतम निश्चित पेंशनः** पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा

THE CORE IAS

- **परिवार पेंशनः** यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है।
- **iii.** यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

- **अभिदाता द्वारा अंशदानः** अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से "ऑटो डेबिट" सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- **केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदानः** पीएम-एसवाईएम 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा

17.''टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत-जर्मन विकास सहयोग के अंतर्गत ''टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन (एसईआईपी)'' परियोजना पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। **यह मंत्रालय और जीआईजेड** –जर्मन विकास एजेंसी का संयुक्त कार्यक्रम है।

18.अमृत शहरों- रायगढ़, अंबिकापुर और कुंभकोणम के नगर निगमों को मिले शीर्ष स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार

- **अमृत शहरों-** रायगढ़, अंबिकापुर और कुंभकोणम के नगर निगमों ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्वछता उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 हासि□ल किया। नगरपालिका परिषद जशपुर नगर, मलप्पुरम नगरपालिका और नगरपालिका परिषद सूरजपुर को वैधानिक शहरों की श्रेणी में पुरस्कार मिले। मिलियन प्लस यानी दस हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए चास नगर निगम को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
-

19.केरल में 'इको सर्किट: पठनमथिट्टा-गवी-वागामोन-थेक्कडी'

- स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के साथ विषयगत सर्किटों का विकास करती है। इस योजना के तहत सरकार जहां एक ओर आगंतुकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

20.राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार

1.	**भारत के प्रधानमंत्री**	**अध्यक्ष (पद के अनुसार)**
2.	**भारत के मुख्य न्यायाधीश**	**सदस्य (पद के अनुसार)**
3.	**लोकसभा में विपक्ष का नेता या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता**	**सदस्य (पद के अनुसार)**
4.	**प्रतिष्ठित व्यक्ति**	**नामित सदस्य**

5.	**प्रतिष्ठित व्यक्ति** **यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों, संघों, संस्थाओं या संगठनों को सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। आम तौर पर, नामांकन से पहले दस वर्षों के दौरान किए गए योगदान पर विचार किया जाता है। पुराने योगदान पर भी विचार किया जा सकता है यदि उनका महत्व हाल ही में स्पष्ट हो गया हो।**	**नामित सदस्य**

21.पीआईएसए (पीसा)

- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)** द्वारा 2021 में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) में भारत की भागीदारी के लिए ओईसीडी के साथ समझौते की वास्तविक स्वीकृति प्रदान की है।
- **लाभ**
- पीसा में भागीदारी से जानकारी प्राप्त करके, स्कूल प्रणाली को योग्यता-आधारित परीक्षा में तब्दील करने में मदद मिलेगी और रट्टा मारकर सीखने की प्रथा से दूरी बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) इस प्रक्रिया और गतिविधियों में हिस्सा लेगा जो कि वास्तविक परीक्षण है।

THE CORE IAS

- **मुख्य विशेषताएं**
- पीसा एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है जो सामग्री आधारित मूल्यांकन के विपरीत है, जिसके द्वारा छात्रों को आधुनिक समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण योग्यता हासिल करने में मदद मिलती है। यह भारतीय छात्रों की मान्यता और स्वीकार्यता को ओर आगे लेकर जाएगा और उन्हें 21 वीं सदी में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) इस प्रक्रिया और गतिविधियों में हिस्सा लेगा जो कि वास्तविक परीक्षण है। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्कूल भाग लेंगे। पीसा में 80 से ज्यादा देशों ने हिस्सेदारी की है, जिनमें 44 मध्यम आय वाले देश हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं।

22.अनियमित जमा योजना अध्यादेश, 2019 पर प्रतिबंध की घोषणा

लाभ :

- प्रस्तावित अध्यादेश से देश में लालची संचालकों द्वारा अवैध रूप से धनराशि जमा कराने से जुड़ी त्रासदी से शीघ्रतापूर्वक निपटा जा सकेगा। ऐसे संचालक फिलहाल नियामक संबंधी कमियों तथा सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का फायदा लेते हुए गरीब और सीधे-साधे लोगों की कड़ी मेहनत से अर्जित धनराशि की ठगी कर लेते हैं। कुल मिलाकर, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा अवैध तरीके से जमाराशि जुटाने के मामले में दंड तथा धन वापसी के लिए पर्याप्त प्रावधान होने से पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी।

23.स्वदेश दर्शन योजना

- थीम-आधारित पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास देश में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. पर्यटन को आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित करना;
2. पर्यटकों की संभावनाओं वाले सर्किटों का योजनाबद्ध और प्राथमिकता से विकास करना;
3. चिन्हित क्षेत्रों में आजीविका के साधनों का सृजन करने के लिए देश के सांस्कृतिक मूल्यों और धरोहरों को प्रोत्साहन देना;
4. सर्किट/गंतव्यों में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं का सतत ढ़ंग से विकास करते हुए वहां के पर्यटन संबंधी आर्कषण को बढ़ाना;
5. समुदाय आधारित विकास तथा गरीब समर्थित पर्यटन दृष्टिकोण का समर्थन करना;
6. स्थानीय समुदायों के बीच आमदनी के स्रोतों में वृद्धि, जीवन के स्तर में सुधार तथा क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना;
7. स्थानीय समुदायों के सक्रिय योगदान के माध्यम से रोजगार सृजन;
8. रोजगार के साधनों के सृजन और आर्थिक विकास की पर्यटन की क्षमताओं का उपयोग करना;

THE CORE IAS

9. थीम आधारित सर्किटों के विकास के माध्यम से देश के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद क्षमताओं तथा उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, राष्ट्रीय संस्कृति और सशक्त विशिष्टताओं के संदर्भ में लाभों का पूर्ण इस्तेमाल करना।

- स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पर्यटन मंत्रालय देश में महत्वपूर्ण पर्यटन अवसंरचना का सतत और समावेशी ढंग से विस्तार कर रहा है ताकि भारत को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जहां निजी क्षेत्र निवेश करने का इच्छुक नहीं है, इनमें अंतिम स्थान तक संपर्क यानि लास्ट माइल क्नेक्टीविटी, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स, सड़क किनारे सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रोशनी का प्रबंध, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधा शामिल है।

24.' राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना '

- विश्व बैंक से ऋण सहायता (आईबीआरडी क्रेडिट) के जरिये दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ' राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना ' नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

लाभ :

- एनआरईटीपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराये जाने वाले उच्च स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल वित एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

THE CORE IAS

मुख्य विशेषताएं:

- डीएवाई-एनआरएलएम निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है। एनआरईटीपी के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने, आजीविका संवर्धन में नवोन्मेषी मॉडलों को प्रस्तुत करने एवं डिजिटल वित की सुविधा एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। डीएवाई-एनआरएलएम पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के बीच परामर्श के लिए आपसी रूप से लाभदायक कामकाजी संबंध और औपचारिक मंच उपलब्ध कराता है। एनआरएलएम ने युक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां एनआरएलएम संस्थान और पीआरआई एक साथ मिल कर काम करेंगे, परस्पर

समन्वय को सुगम बनाने के लिए गतिविधि मानचित्र भी विकसित किया है जिसे सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को प्रसारित कर दिया गया है.

25.अरूणाचल प्रदेश में सेला टनल

26.मथुरा जिले में मेगा फूड पार्क की आधारशिला

27.अटल नवाचार मिशन

- एडोब अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) पहल के अंतर्गत 100 स्कूलों को गोद लेगी। एटीएल में एडोब डिजिटल दिशा कार्यक्रम लागू करेगी, जिसके अंतर्गत एटीएल को एडोब स्मार्क प्रीमियम का निःशुल्क लाइसेंस पेश किया जाएगा। 2018 में लॉच किए गए एडोब डिजिटल दिशा कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक सोच और टेक्नोलॉजी आधारित ज्ञान के बीच आपसी क्रियाकलाप को प्रेरित करना है। एआईएम के साथ इस सहयोग के अंतर्गत इन स्कूलों के बच्चे और शिक्षक तथा समुदाय के लोग रचनात्मक ज्ञान संसाधनों का लाभ उठाएंगे जिससे वह वर्तमान डिजिटल युग में कौशल संपर्क बनेंगे और दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयारी करेंगे.
- एआईएम देश में नवाचार तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने का भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है। एआईएम के हिस्से के रूप में भारत में 5000 से अधिक स्कूलों में एटीएल स्थापित किए जा रहे है जहां छठी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी समस्या समाधान के उपाय तथा नवाचार कौशल प्राप्त करेंगे और 3डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स, छोटे इलेक्ट्रोनिक्स, आईओटी तथा प्रोग्रामिंग जैसी टिंकरिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर नवाचारी समाधान विकसित करेंगे।
- अटल टिंकरिंग लैब का दर्शन देश के युवा विद्यार्थियों में नवाचार की पहचान करके उनको बढ़ावा देना है। इस प्रयास में एआईएम ने उद्योग और शिक्षा जगत के विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग किया है। ऐसे सहयोग से भविष्य के कौशल तथा एटीएल प्रणाली की डिजिटल क्षमताओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

THE CORE IAS

28.स्वच्छ गंगा कोष

- स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना संस्थानों और व्यक्तियों को जोड़ने और उनके योगदान के लिए जनवरी-2015 में एक न्यास के रूप में की गई थी, जिसके केन्द्रीय वित्त मंत्री पदेन अध्यक्ष है। घरेलू स्तर पर सीजीएफ में योगदान करने वाले को आयकर कानून **1961 की धारा 80जी (1)(**i) के अंतर्गत आयकर में शत-प्रतिशत छूट मिलती है।

- स्वच्छ गंगा कोष को समर्थन देने और एनआरआई से जोड़ने के लिए **'प्रवासी गंगा प्रहरी कार्यक्रम'** की शुरूआत की गई। कार्यक्रम की एक अन्य विशेषता के रूप में विदेशी नागरिकों की गंगा के संरक्षण में दिलचस्पी देखने को मिली।

29."वन धन योजना"

- जनजातीय कार्य मंत्रालय अब "वन धन योजना" का विस्तार कर रहा है और उसे चरणबद्ध रूप से देश के सभी जनजातीय जिलों में लागू करने के लिए तैयार है। इसकी शुरूआत बड़ी जनजातीय आबादी वाले महत्वाकांक्षी जिलों के साथ की जाएगी। 'सूक्ष्म वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं वन धन के मूल्य वर्धन संघटक"' का शुभारंभ करेंगे। ट्राइफेड ने सीएसआर निधियां एकत्र करने के लिए "फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स" योजना भी प्रारंभ की है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण करने का अनुरोध किया गया है।

30.आईएसएल शब्दकोश

- **इंडियन साईन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आईएसएलआरटीसी)** सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह शब्दकोश आईएसएल शिक्षकों, आईएसएल छात्रों, भाषा संकेतकों ,बधिर व्यक्तियों और शोध करने वालों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस शब्दकोश को बधिर समुदाय के लोगों के सुझावों और समझ के आधार पर तैयार किया गया है। अंग्रेजी और हिन्दी संकेतों की सूची भी दी गई है। **2011 की जनगणना** के अनुसार भारत में **50.71 लाख बधिर** व्यक्ति हैं। शब्दकोश निर्माण का लक्ष्य आईएसएल के उपयोग को बढ़ाना और बधिर व्यक्तियों को शिक्षा तथा रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।

31.'सतत'योजना

- सतत' योजना के तहत **संपीड़ित जैव-गैस (कंप्रेस्ड बायो गैस या सीबीजी)** उद्यमी (उत्पादक) **सतत'** एक पहल है जिसका उद्देश्य विकास से जुड़े एक ठोस प्रयास के रूप में किफायती परिवहन या आवाजाही के लिए टिकाऊ विकल्प मुहैया कराना है जिससे वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के साथ-साथ किसान एवं उद्यमी भी लाभान्वित होंगे।

32.अप्रेंटिसशिप एवं कौशल (श्रेयस) योजना

- राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना (एनएपीएस) के माध्यम से अप्रैल 2019 में निकलने वाले सामान्य स्नातकों को उद्योग में अप्रेंटिसशिप का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल (श्रेयस) योजना शुरू की है। किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को 'जॉब वर्क एक्सपोजर' और कमाई का अवसर उपलब्ध कराते हुए रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

33.फेम इंडिया योजना दूसरे चरण

- यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा 'फेम इंडिया वन' का विस्तारित संस्करण है। 'फेम इंडिया वन'योजना 1 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी।

वित्तीय प्रभावः

- फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

प्रभावः

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है। यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

THE CORE IAS

विवरणः

- बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर।
- इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, ऐसे खर्च राज्य और शहरी परिवहन निगमों द्वारा दिया जाना।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वॉट और 4 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि।
- 2 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केन्द्रित रखना।
- इस योजना के तहत 2 वॉट वाले 10 लाख, 3 वॉट वाले 5 लाख, 4 वॉट वाले 55,000 वाहन और 7000 बसों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की योजना है।

- नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयोन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैट्रियां लगाई गई हों।
- योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में तीन किलोमीटर के अंतराल में 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव हैं।
- बड़े शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।
- ऐसे राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ भी ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।

34.प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना

विवरणः

- इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।
  - पहला चरण (2018-19 से 2022-23)- इस अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
  - दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24)- इस अवधि में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।
- परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है। इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करने और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
- ईबीपी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुंचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी होंगे।
  - जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।

THE CORE IAS

- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के सीएचजी मानक की प्राप्ति।
- बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
- दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।

- योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, ताकि वे ईबीपी कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सके।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इथेनॉल की कीमत ज्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान इथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही, हालांकि यह देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल के 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिए पर्याप्त है। इथेनॉल इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही हैं। इससे ईबीपी कार्यक्रम के तहत किसी तरह होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना इसी को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। इसके तहत देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
- इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक प्रोजेक्ट डेवलपरों को अपने प्रस्ताव समीक्षा के लिए मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को सौंपने होंगे। समिति जिन परियोजनाओं की अनुशंसा करेगी उन्हें मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

<u>पृष्ठभूमिः</u>

- भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के

THE CORE IAS

इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है। वर्तमान में ईबीपी 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है। मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्टाक उत्पादों जैसे सेलुलोसेस और लिग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

35.गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान की आधारशिला

36.टेक-सोप' 2019

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के **मध्य जागरूकता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा और अवसरों का सृजन करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तकनीकी, प्रौद्योगिकी सहायता और आउटरीच (टेक-सोप 2019) के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।**

MAINS SPECIAL

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय-

- कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर भारत की आयात पर निर्भरता सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय रही है। हालांकि हमने बायोईंधन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से बढ़ती हुई मांग को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। फिर भी आयात कम करने के लिए हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। समिति की सिफारिशों में खोज के लिए बोली की प्रणाली में बदलाव लाना और श्रेणी 2 और श्रेणी 3 बेसिनों के खोज कार्यक्रमों के लिए राजस्व साझा करने में परिवर्तन लाना शामिल है।

- **उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन**
- अंतरिम बजट के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हम स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत की महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहणी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए यह भी जरूरी है कि महिला अपने परिवार के पोषण के लिए खाना पकाते समय आंसू न बहाए।

- **<u>पेट्रोलियम सब्सिडी, पीओएल का आयात</u>**-बजट दस्तावेजों के साथ एफआरबीएम अधिनियम के तहत दिए गए विवरणों में बताया गया है कि पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स (पीओएल) का आयात अप्रैल–दिसंबर, 2018 की अवधि में 42.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण 108.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर का रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह आयात 75.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा था। ऐसा मुख्य रूप से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ।

- **<u>12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वैच्छिक रूप से पीडीएस मिट्टी का तेल आवंटन छोड़ा</u>**
- 12 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (कर्नाटक, हरियाणा,तेलंगाना, नगालैंड, चंडीगढ़, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, पुद्दुचेरी, राजस्थान और महाराष्ट्र) ने केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटीके) के तहत अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिट्टी के तेल के आवंटन को स्वैच्छिक रूप से छोड़ दिया है। आज की तारीख के अनुसार 8 राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल आवंटन को छोड़ दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल का कोटा स्वैच्छिक रूप से छोड़ने वाले राज्यों को मिट्टी के तेल का आवंटन नहीं किया गया है।

<u>2. साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार हुए 40 युवकों के लिए बेंगलूरु में 'नो माई इंडिया' कार्यक्रम के तहत विशेष कार्यशाला</u>

THE CORE IAS

- बीते समय साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार हुए 15 से 22 वर्ष आयु वर्ग के 42 युवाओं के लिए **<u>राष्ट्रीय नेशनल फाउंडेशन फॉर कमयूनल हार्मोनी</u>** – एनएफसीएच की ओर से ***<u>'नो माई इंडिया कार्यक्रम'</u>*** के तहत कल से बेंगलूरु में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में जम्मू कश्मीर,मणिपुर,असम,छत्तीसगढ़,बिहार और गुजरात जैसे छह राज्यों के युवा अपने आधिकरिक मेंटरों के साथ हिस्सा लेंगे।
- कार्यशाला का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले युवाओं को हिंसा के कारण उपजे संघातिक तनाव से निबटने में मदद करने के साथ ही उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और बुरे अनुभवों से निजात पाने में मदद करना है। इस दौरान उन्हें तनाव से मुक्त असीम शांति का अनुभव कराया जाएगा और साथ ही उनमें विश्व के प्रति एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास भी किया जाएगा। कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों के जरिए

परस्पर संपर्क और संवाद की कला भी सिखायी जाएगी। इसमें सशक्त श्वसन क्रिया, सुदर्शन पर विशेष जोर रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इसके नियमित अभ्यास से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन में काफी कमी आती है। दिमाग स्वस्थ होता है और शांति महसूस होती है।

- एनएनएफसीएच की ओर शुरु किया गया '**नो माई इंडिया** 'कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसके जरिए विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के आर्थिक मदद पाने वाले बच्चों के बीच एकजुटता ,सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है जिसमें वह एक दूसरे की सामाजिक रीति रिवाजों और पारिवारिक जीवन शैली के बारे में जान सकें तथा उनमें देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों की अच्छी समझा विकसित हो सके।
- एनएफसीएच गृहमंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित एक स्वतंत्र निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा का शिकार हुए बच्चों और युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान कर उनका पुनर्वास करने के साथ ही उन्हें बीती घटनाओं के बुरे अनुभवों से मानसिक तौर पर निजात दिलाना है। इसके लिए नएएफसीएच समय समय पर स्वतंत्र रूप से और कई बार शिक्षण संस्थाओं के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का आायोजन कर साम्पद्रायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने का काम करता है।

THE CORE IAS

3. कृषि निर्यात नीति पर आधारित पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम पुणे में आयोजित

- कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने चुनिंदा उत्पादों की मांग बढ़ाने के क्रम में आकर्षक पैकेजिंग पर भी जोर दिया। भारतीय पैकेजिंग संस्थान अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए स्तरीय पैकेजिंग के काम में जुटा है।
- भारत सरकार ने हाल में एक कृषि निर्यात नीति जारी की है। इसका लक्ष्य निर्यात आधारित कृषि उत्पाद और प्रसंस्करण से लेकर परिवहन, आधारभूत सुविधा और बाजार पहुंच तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। कृषि निर्यात नीति में निर्यात आधारित कृषि उत्पादन, निर्यात संवर्धन, भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार खेती को बेहतर रूप में व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है।

- भारत में प्रतिवर्ष लगभग **600 मिलियन टन** कृषि और बागवानी उत्पादन होता है तथा बागवानी उत्पादों का 30 प्रतिशत हिस्सा खराब हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की क्षति से बचने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। उत्पादों को हमारी अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं रखा जाना चाहिए और इसलिए भारत के कृषि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश करने की आवश्यकता है।हमें उत्पादन के दौरान ही गुणवत्ता मानदंडों और स्वास्थ्य मानदंडों पर विचार करना होगा। कृषि को एक अन्य उद्योग के रूप में देखने की जरूरत है और इसकी सफलता के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उद्योगपतियों को भी कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।

4.ओडिशा में 12वां क्षेत्रीय मानक सम्मेलन

- **बीआईएस कानून 2016** भारत में मानकों के विकास और अंतरण की रूपरेखा निर्धारित करता है। देश में अंतरित किये जाने वाले उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला तथा उपभोक्ता और उत्पादकों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए।इसका आयोजन भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) ने ओडिशा सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशल बॉडीज (एनएबीसीबी), निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र (सीआरआईटी) के सहयोग से किया था।

THE CORE IAS

5.आपदा जोखिम प्रबंधन पर इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन की बैठक

- इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन एक अंतर-सरकारी संगठन है और उसमें 22 सदस्य तथा 9 संवाद साझीदार शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे देश हैं, जहां प्रायः आपदा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। डीआरएम इस संगठन के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल है और उसकी कार्य योजना (2017-2021) का उद्देश्य आईओआरए देशों में आपदा प्रबंधन में सुधार लाना है।

6.श्रम मंत्रालय ने खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने के लिए नियम अधिसूचित किए

अब खदानों में महिलाओं को रोजगार के समान अवसर

- खान अधिनियम, 1952 की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के तहत खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोजगार प्रदान करने की छूट दी है:-
- जमीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में-
- खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है।
- महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
- ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।
- जमीन के नीचे स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में-
- खदान-मालिक महिलाओं को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक तकनीकी, निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता हैं जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो।
- महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
- ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।

7.नदी सूचना प्रणाली-आरआईएस (फरक्का-पटना)

- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर 410 किलोमीटर लंबे फरक्का-पटना मार्ग पर नदी सूचना प्रणाली के दूसरे चरण का उद्घाटन होने से इस मार्ग पर चलने वाले जहाजों और नदी किनारे बने आधार स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक डाटा का तेज गति से आदान-प्रदान हो सकेगा। यह एक प्रकार की जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से जहाजों के बीच टक्कर, जहाज और पुल के टकराने की घटनाओं को रोकने तथा जल परिवहन से जुड़ी सभी

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। यह प्रणाली यूरोप, चीन और अमरीका जैसे देशों में उन्नत जल परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नदी सूचना प्रणाली के दूसरे चरण में– मनिहारी, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़ और हतिदह में पांच आधार स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पटना में एक कंट्रोल स्टेशन बनाया गया है। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण इस परियोजना को तीन चरणों में लागू कर रहा है।

फरक्का नेवीगेशन लॉक की मदद से हिल्सा मछलियों का संरक्षण

- विकास का पर्यावरण अनुकूल टीकाऊ सुरक्षित और किफायती मॉडल विकसित करने की भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की प्रतिबद्धता के अनुकूल फरक्का में बनाया गया नेवीगेशन लॉक गंगा नदी में हिल्सा मछलियों के प्रजनन और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आसान बनाएगा। फरक्का नेवीगेशन लॉक के तहत जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए नदी में हिल्सा मछलियों के लिए अलग से गलियारा बनाया गया है। 1976 में फरक्का नेवीगेशन लॉक के निर्माण के बाद से नदी में हिल्सा मछलियों की गतिविधियां फरक्का तक सीमित रह गई थी, लेकिन अब जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए अलग से मछलियों के गलियारा बन जाने से इनका एक स्थान से दूसरे स्थान आना-जाना आसान हो गया है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी हिल्सा का काफी सांस्कृतिक महत्व है।
- मछलियों के लिए बनाए जाने वाला विशेष गलियारा बांधों और झरनों के आसपास बनाया जाता है, ताकि मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने के लिए प्राकृतिक माहौल मिल सके।

THE CORE IAS

8.राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति -2019

- नीति में चिपसेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बना कर भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम)' के एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

एनपीई 2019 की मुख्य बातें

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा: ईएसडीएम की समूची मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जो के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी।

- ऐसी मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज दिया जाएगा, जो अत्यंत हाई-टेक हैं और जिनमें भारी-भरकम निवेश की जरूरत है। इनमें सेमी कंडक्टर सुविधाएं, डिस्प्ले फैब्रिकेशन इत्यादि शामिल हैं।
- नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों के विस्तारीकरण के लिए उपयुक्त योजनाएं और प्रोत्साहन देने से जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें बुनियादी या जमीन स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे कि 5जी, आईओटी/सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियल्टी (वीआर), ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरणों इत्यादि के क्षेत्र में प्रारंभिक चरण वाले स्टार्ट-अप्स भी शामिल हैं।
- कुशल श्रमबल की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगारों का कौशल फिर से सुनिश्चित करना भी शामिल है।
- फैबलेस चिप डिजाइन उद्योग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और मोबिलिटी एवं रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- ईएसडीएम क्षेत्र में आईपी के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन पेटेंट फंड (एसपीएफ) बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) से जुड़ी पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

THE CORE IAS

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (एनपीई 2012) के तत्वावधान में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से एक प्रतिस्पर्धी भारतीय ईएसडीएम वैल्यू चेन से जुड़ी नींव सफलतापूर्वक मजबूत हो गई है। एनपीई 2019 में इस नींव को और मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि देश में ईएसडीएम उद्योग के विकास की गति तेज की जा सके। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (एनपीई 2019) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (एनपीई 2012) का स्थान लिया है।

कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

- **कार्यान्वयन रणनीति:** इस नीति से इसमें परिकल्पित रोडमैप के अनुसार ही देश में ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं एवं उपायों को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

- **लक्ष्य :** वर्ष 2025 तक 400 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 26,00,000 करोड़ रुपये) का कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ईएसडीएम की समूची वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें वर्ष 2025 तक 190 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 13,00,000 करोड़ रुपये) मूल्य के एक अरब (100 करोड़) मोबाइल हैंडसेटों का लक्षित उत्पादन शामिल होगा। इसमें निर्यात के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 7,00,000 करोड़ रुपये) मूल्य के 600 मिलियन (60 करोड़) मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना भी शामिल है।

प्रमुख प्रभाव

- एनपीई 2019 को कार्यान्वित करने पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से देश में ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं इत्यादि को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे भारत में निवेश एवं प्रौद्योगिकी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे देश में ही निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ज्यादा मूल्य वर्धन और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनके निर्यात का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

9.विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव

- देश के सर्वाधिक वंचित नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विमुक्त घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय (डीएनसी) देश के सबसे अधिक वंचित समुदाय हैं। इन समुदायों तक पहुंच बनाना मुश्किल है, ये ज्यादा दिखाई नहीं देते और इसलिए अक्सर छूट जाते हैं। जहां अधिकतर विमुक्त घुमंतू समुदाय अनुसूचित जातियों (एससी) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल हैं, इसके बावजूद कुछ विमुक्त घुमंतू समुदाय किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणियों में कवर नहीं किये गये हैं।
- इसलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है ,जो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के)डीएनसीएस) लोगों की पहचान की प्रक्रिया को पूराकरेगी, जिन्हें अ ब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के)डीएनसीएस) लोगों की राज्य-वार सूची को तैयार करने तथा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बारे में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उचित उपाय सुझाने के लिए सरकार ने जुलाई 2014 में तीन वर्ष की अवधि

के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपना कार्य .09 01.2015 को शुरू किया और अपनी रिपोर्ट 8जनवरी 2018 को सौंप दी।

- आयोग ने इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी । चूंकि अधिकांश डीएनटी को एससी,एसटी या ओबीसी के अंतर्गत कवर किया गया है, ऐसे

  में उनके विकास कीयोजनाओं को लागू करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना कर ना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा ,बल्कि यह शिकायत निवारण करेगा तथा इसलिए इसका

  अनुसूचित जाति के लिए) राष्ट्रीय अनुसूचित जातिआयोग(, अनुसूचित जनजाति के) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग) जैसे मौजूदा आयोगों के साथ टकराव होगा। इसके बाद सरकार नेयह निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में सं स्था पंजीकरण अधिनियम ,1860 के तहत एक विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थाप ना की जाए, जिसके माध्यम सेविमुक्त, घुमंतू और अर्ध-
  घुमंतू समुदायों)डीएनसीएस) के लोगों के विकास और कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।
- आयोग द्वारा तैयार की गई समुदायों की राज्यवार सूची इस आशय से पूरी नहीं है क्योंकि कुछ समुदायों के बारे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें और अधिक विधिमान्यकरण की आवश्यकता है।

10.किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का शुभारंभ

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम, केयूएसयूएम) का शुभारंभ करने की मंजूरी दी।
- प्रस्तावित योजना के तीन घटक हैं :
- घटक ए : नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से 10,000 मेगावाट के भूमि के ऊपर बनाए गए विकेन्द्रीकृत ग्रिडों को जोड़ना।घटक ए और घटक सी को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।
- घटक बी : 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों को लगाना।
- घटक सी : 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरकरण।

प्रभाव

- इस योजना से कार्बन डाईआक्साइड में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। योजना के तीनों घटकों को सम्मिलित करने में पूरे वर्ष में कार्बन

डाईआक्साइड उत्सर्जन में 27 मिलियन टन की कमी आएगी। घटक बी के अंतर्गत सौर कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीजल की बचत होगी। इससे कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

- इस योजना में रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। स्व-रोजगार में वृद्धि के साथ इस योजना से कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए 6.31 लाख रोजगार के नए अवसरों के सृजन होने की संभावना है।

11.डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप से जुड़ी पहलों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण लांच

- राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के प्रथम संस्करण में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था।
- रैंकिंग रूपरेखा (फ्रेमवर्क) 2019 में 7 आधार और 30 कार्य-बिंदु शामिल हैं। इन आधारों के जरिए संस्थागत सहायता, नियम-कायदों को सरल करने, सार्वजनिक खरीद को आसान करने, इन्क्यूबेशन संबंधी सहयोग, प्रारंभिक पूंजी के वित्त पोषण संबंधी सहयोग, उद्यम वित्त पोषण संबंधी सहायता एवं जागरूकता और पहुंच संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन किया जाता है।

12.मेगा फूड पार्क

- **अगरतला के गांव तुलकोना में सिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह त्रिपुरा राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है।**
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मूल्यवर्धन करने और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपशिष्ट को कम करने में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, देश में मेगा फूड पार्क योजना को लागू कर रहा है। मेगा फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक मजबूत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से ,फॉर्म से बाजार तक, अगले और पिछड़े लिंकेज के साथ ही, मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं का निर्माण करता है। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाओं और सक्षम बुनियादी ढाँचाओं का निर्माण किया जाता है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों)पीपीसी (और संग्रह केंद्रों) सीसीएस (में प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए फॉर्म के पास सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार, प्रत्येक मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है.

THE CORE IAS

13.पुलिस सेवाओं का 'ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे'

- नागरिक केन्द्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के संबंध में राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को मजबूती देने के मद्देनजर सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती है। इसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां जन-आकांक्षा संबंधी सर्वेक्षण के जरिए उपरोक्त प्रयासों का विश्लेषण करती हैं। ऐसे सर्वेक्षण दुनिया भर में किए जाते हैं।
- सरकार और जनता के बीच सुशासन के मॉडल को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 'ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेस' नामक यह सर्वेक्षण नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद करेगा और सर्वेक्षण नौ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

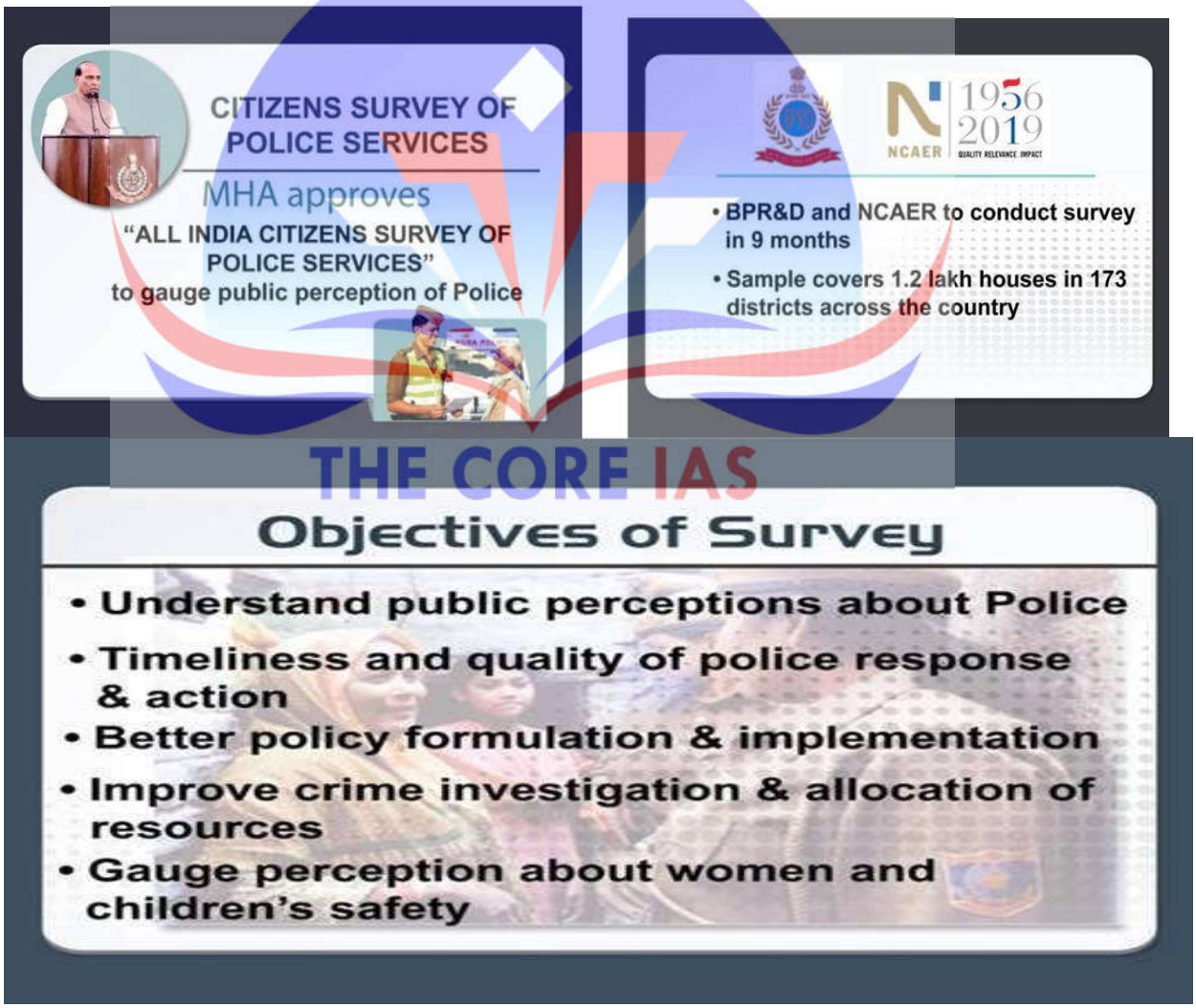

- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पुलिस के बारे में लोगों के विचारों और उनके रवैये को समझना है। इसके तहत यह देखा जाना है कि ऐसे अपराधों और घटनाओं की तादाद कितनी हैं, जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की जाती है।
- सर्वेक्षण मध्य मार्च 2019 में शुरू होगा और इसके दायरे में देश के 173 जिलों के 1.2 लाख घर होंगे। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा के अनुरूप होगा। सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सर्वेक्षण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

14.'शिष्ट भारत अभियान'

- वरिष्ठ लोगों को अपने आचरण से युवा पीढ़ी के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि युवा अपनी पुरानी पीढ़ियों को देखकर स्वभाविक रूप से मूल्यों को प्राप्त कर सकें। इस आयोजन की थीम- स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक विज्ञान शिक्षा के महत्व पर चर्चा करना और पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल करना था। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मूल्यों को बदलने में तीन पीढ़ियां लगती हैं, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों में अच्छे मूल्यों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक गतिशील लोकतंत्र है और इन बदलावों को अपनाना सीखकर हम लाभ उठा सकते हैं।

15.ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरूआत की

- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक क्रांतिकारी कदम है, जो अध्ययन के साथ-साथ अध्यापन की प्रक्रिया को संवादमूलक बनाएगा तथा शिक्षा-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण के रूप में अध्ययन को लोकप्रिय बनाएगा। डिजिटल बोर्ड देशभर के सरकारी और सरकारीसहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू किया जाएगा। यह प्रक्रिया 2019 के आगामी सत्र से शुरू हो जाएगी।
- ओडीबी का उद्देश्य कक्षा को डिजिटल क्लास रूम में बदलना है और साथ ही छात्रों को किसी भी स्थान पर किसी भी समय ई-संसाधन उपलब्ध कराना है। इससे व्यक्तिगत अनुकूलनीय ज्ञान के साथ-साथ मशीन ज्ञान,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अनेलेटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का दोहन करके कुशल अध्यापन का प्रावधान करने में मदद मिलेगी। एक विशेषज्ञ समिति ने ओडीबी के अंतर्गत डिजिटल क्लास रूम के अधिकतम विन्यास तैयार कर लिया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ***ई-पाठशाला, दीक्षा,एनआरओईआर, एनपीटीईएल, ई-पीजीपाठशाला स्वयं और स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल*** आदि ने उच्च गुणवत्ता की पर्याप्त सामग्री प्रदान की है जिसे प्रत्येक कक्षा तक ले जाया जा सकता है। इस प्रकार के शैक्षणिक हस्तक्षेप से अध्यापन का

स्तर बेहतर हो सकता है चाहे स्कूल और कॉलेज/संस्थान कहीं भी हो इस तरह के प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान से देश भर के अध्यापकों को प्रेरणा मिल सकती है और वे अपना अध्यापन के स्तर बेहतर कर सकते हैं।

- उच्च शिक्षण संस्थानों में ओडीबी के लिए यूजीसी कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- यह अनुमान लगाया गया कि संस्थानों में 5 लाख क्लास रूम होंगे जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जाएगी।]

16.दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

- महात्मा गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रही है। दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य की भाषा सीखना बहुत शिक्षाप्रद हो सकता है। इसके माध्यम से नई-नई संस्कृतियों को जानने और समझने के लिए बेहतरीन अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के बीच सहयोगी कार्यक्रमों के जरिए एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की भाषा लोकप्रिय हो रही है। इस कदम से राष्ट्रीय समरसता को मजबूती मिलती है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुब्रमण्या भारती की कविताओं से न केवल तमिलनाडु के, बल्कि पूरे देश के लोग प्रेरित हुए थे। इसी तरह पेरियार के मुक्ति आदर्शों ने मानव गरिमा को नई ऊंचाईयां दीं। यह आदर्श भाषा या भूगोल तक सीमित नहीं रहे।
- दूसरे राज्यों की भाषा सीखने से व्यावहारिक लाभ होता है। हम लोग ऐसे युग में रह रहे हैं, जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत के भीतर लोगों का आवागमन तेज हो रहा है। युवा लोग देश के एक हिस्से से निकलकर देश के दूसरे हिस्से में अध्ययन कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं। इस तरह जो व्यक्ति जहां काम करता है या जहां पढ़ रहा है, वहां की भाषा सीखने से उसे बहुत लाभ होगा।

THE CORE IAS

17.सिंधु नदी जल संधि 1960 : भारत में वर्तमान स्थिति

- सिंधु प्रणाली में मुख्यत **सिंधु , झेलम, चेनाब,रावी, ब्यास और सतलुज नदियां** शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र (बेसिन) को मुख्यत भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच **1960** में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। रावी, सतलुज और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का औसत **33 मिलियन (एमएएफ)** पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया।

इसके साथ ही पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम और चेनाव नदियों का करीब 135 एमएएफ पाकिस्तान को दिया गया।

- समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया।

भारत में वर्तमान स्थिति

- जल संधि के तहत जिन पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था उसका उपयोग करते हुए भारत ने सतलुज पर भांखड़ा बांध, ब्यास नदी पर पोंग और पंडु बांध और रावी नदी पर रंजित सागर बांध का निर्माण किया। इसके अलावा भारत ने इन नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ब्यास-सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर-ब्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी बनाई। इससे भारत को पूर्वी नदियों का करीब 95 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल करने में मदद मिली। हालांकि इसके बावजूद रावी नदी का करीब 2 एमएएफ पानी हर साल बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर चला जाता है। इस पानी को रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाएं हैः-

- **शाहपुरखांडी परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू करनाः**
- **उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना**
- **उझ के नीचे दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना**

THE CORE IAS

18.राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के विन्यास में चार संकेंद्री वृत्त शामिल हैं, जिनके नाम हैं 'अमर चक्र', 'वीरता चक्र', 'त्याग चक्र' और 'रक्षक चक्र'।
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक केंद्रीय चतुष्कोण स्तंभ, एक शाश्वत लौ, और भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों को दर्शाती छह कांस्य भित्ति चित्र शामिल हैं।
- परम वीर चक्र के 21 पुरस्कार विजेताओं की अर्धप्रतिमा परम योद्धा स्टाल पर लगाई गई हैं, जिसमें तीन जीवित पुरस्कार विजेता सूबेदार (मानद कैप्टन) बाना सिंह (सेवानिवृत्त), सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं।
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है।

19.बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रतिस्पर्धा 'आईप्रिज्म'

- आईपी जागरुकता पैदा करना आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हो गया है। जहां नवोन्मेष विकास और राष्ट्र की सफलता निर्धारित करता है। जागरुकता पैदा करने से न केवल छात्र नवोन्मेष और उसकी असीमित संभावनाओं के प्रति प्रेरित होते है बल्कि आईपी अधिकारों के संबंध में सम्मान पैदा करने में मदद मिलती है बल्कि जालसाझी और पाइरेसी को भी रोका जा सकता है।

20.सीआईआई और आईआईसीए के बारे में

- बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) की स्थापना वर्ष 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और उसे बरकरार रखना है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और भारत के बाजारों में व्यापार की आजादी सुनिश्चित हो सके।
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कंपनी जगत की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मामलों को निपटाना है। साथ ही यह सरकार, नियामकों, पेशेवरों और आम लोगों से आने वाले व्यापक हितधारकों में क्षमता निर्माण के लिए निर्देश जारी भी करता है।

20.चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सोझेदारी सम्मेलन

- डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक अंतर-सरकारी सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा वैश्विक स्वास्थ्य डिजिटल साझेदारी (जीडीएचपी) के सहयोग से किया जा रहा है।

21. इंडिया -कोरिया

- भारत और कोरिया के सम्बन्धों का आधार सिर्फ business contact ही नहीं है, इसका मुख्य आधार है people to people contact. देश से आए या फिर यहीं रह रहे आप सभी भारतीय हमारे सम्बन्ध की बुनियाद हैं। राजदूत तो एक होता है, लेकिन राष्ट्रदूत अनेक होते हैं। भारत और कोरिया के बीच आत्मीयता का ये सम्पर्क नया नहीं है। प्राचीन काल में भारत की राजकुमारी सूर्यरत्ना हजारों किलोमीटर की यात्रा कर-करके यहां पहुंची थी। उनका विवाह यहां के राजा से हुआ। आज भी लाखों कोरियाई अपने-आपको उनके वंशज मानते हैं; और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कोरियाई समाज से एक प्रकार से हम लोगों का खून का रिश्ता है। भारत और कोरिया के समबन्धों

को बौद्ध धर्म ने भी बहुत ताकत दी बहुत सशक्त बनाया। एक कोरियाई बौद्ध भिक्षुक हाइचो ने 8वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी।

(प्रधानमंत्री के भाषण का अंश)

22. 'दिल्ली घोषणा'

- इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन को नेतृत्व की भूमिका निभानी है और सदस्य देशों को सहायता देने के लिए केंद्रीय रूप से समन्वित डिजिटल स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था स्थापित करनी है। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रभाव पर विचार करने के लिए 34 से अधिक देशों के मंत्री तथा सरकारी अधिकारी शामिल हुए।
- डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक अंतर-सरकारी बैठक का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) तथा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप (जीडीएचपी) के सहयोग से किया।

23.राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

लाभ

- नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी। यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होनेवाले लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी।

THE CORE IAS

उद्देश्य

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है।

ब्यौरा

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जैसे-
- आरपी/पीएल धारकों के लिए पहले अस्वीकार के अधिकार की शुरूआत
- अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना
- राजस्व-साझा के आधार पर समग्र आरपी-सह-पीएल-सह-एमएल के लिए नये क्षेत्रों में नीलामी

- खनन कंपनियों में विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन तथा खनन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन-पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति तथा समर्पित खनिज कॉरीडोर का निर्माण
- 2019 नीति में प्रस्ताव दिया गया है कि खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे निजी क्षेत्र को खनन-संपत्ति अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा।
- यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति के निर्माण से निजी क्षेत्र बेहतर नीतियां बनाने में सक्षम होगा और व्यापार में स्थिरता आएगी।
- नीति में सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए आरक्षित क्षेत्रों को भी युक्तिसंगत बनाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे क्षेत्रों जहां खनन गतिविधियों की शुरूआत नहीं हुई है की नीलामी होनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
- नीति में निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक मानदंडों के आधार पर टैक्स, लेवी और रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में कुछ बदलाव किये गए हैं जैसे नीति के विजन के रूप में मेक इन इंडिया और लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना। खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आई-टी सक्षम प्रणाली, जागरूकता तथा सूचना अभियान आदि को शामिल किया गया है। स्वीकृति मिलने में विलंब होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे प्रावधान शामिल किये गए हैं जिससे उच्च-स्तर पर मामलों को निपटाया जा सकेगा। एमएनपी, 2019 का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। खनन पट्टा-भूमि प्रणाली के तहत खनिज संसाधनों तथा पट्टे पर दी गई भूमि का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नई नीति के तहत खनिजों के परिवहन के लिए तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति में खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज कॉरीडोर का उल्लेख किया गया है। परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और निवासियों के न्यायसंगत विकास के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग की बात कही गई है। एमएनपी, 2019 में खनिज क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के आयात-निर्यात नीति का प्रस्ताव दिया गया है। इससे खनिज गतिविधि में स्थिरता आएगी और बड़े पैमाने पर होने वाली वाणिज्यिक खनिज गतिविधि में निवेश आकर्षित होगा।
- नीति, 2019 में अंतर-पीढी समानता के विचार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के कल्याण की बात कहीं गई है। नीति

THE CORE IAS

में अंतर-मंत्रालय निकाय के गठन का भी उल्लेख है जो सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।

24.नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक

लाभ

- इस संस्थागत मध्यस्थता के लाभ सरकार, उसकी संस्था और परिवाद के पक्षकारों को प्राप्त होंगे। विशेषज्ञता की गुणवत्ता और आने वाली लागत के लिहाज से यह केंद्र जनता और सरकारी संस्थानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और भारत के संस्थागत मध्यस्थता की धुरी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

उद्देश्य

- एनडीआईएसी को जिन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जाएगा वो हैं –
- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता संचालित करने के एक प्रमुख संस्थान के तौर पर खुद को विकसित करने के लिए लक्षित सुधार लाना।
- समाधान मध्यस्थता और मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासकीय सहयोग प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त पंचों, मध्यस्थों व सुलहकारों या सर्वेक्षकों और जांचकर्ताओं जैसे विशेषज्ञों के पैनल बनाकर रखना।
- बड़े ही पेशेवर अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थताओं और सुलहों के संचालन को सुगम बनाना।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और सुलह के संचालन के लिए कम खर्चीली और समयोचित सेवाएं प्रदान करना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में अध्ययन को प्रोत्साहित करना और झगड़ों के निपटारे की व्यवस्था में सुधारों को प्रोत्साहित करना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाजों, संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।
- एनडीआईएसी की स्थापना को सुगम करने की दिशा में इस विधेयक में, वैकल्पिक विवाद समाधान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएडीआर) के दायित्वों को केंद्र सरकार में स्थानांतरित और निहित करने की परिकल्पना की गई है। केंद्र सरकार बाद में ये दायित्व एनडीआईएसी में निहित करेगी।

मुख्य विशेषताएं

THE CORE IAS

- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या फिर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों जिन्हें मध्यस्थता कानून के प्रशासन या प्रबंधन या संचालन में अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो। उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- दो पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य इसमें होंगे जिन्हें उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से लिया जाएगा जिन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, संस्थागत मध्यस्थता का ठोस ज्ञान और अनुभव हो।
- साथ ही, वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को नियमित आवर्तन के आधार पर अंशकालिक सदस्य के तौर पर चुना जाएगा।
- विधि मामलों के विभाग के सचिव, व्यय विभाग द्वारा नामित वित्तीय सलाहकार और एनडीआईएसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे।

THE CORE IAS

USEFUL IN MAINS-

- उच्च शिक्षा में समानता को सुरक्षा करना और बढ़ावा देना हमारे लिए आवश्यक है : उपराष्ट्रपति

  सोच, कर्म और मन से सभी शिक्षकों का संपूर्ण विकास होना शिक्षा का लक्ष्य हो

  उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए

  हमारे बच्चों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर हमें अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए

  भारत जीवन में बदलाव लाने वाली डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है ; प्रौद्योगिकी से शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है
- **2.** उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि हर काल में पत्रकारिता एक मिशन रही है जिसने समाज के खिलाफ ताकतों से हमेशा संघर्ष

किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन आज यह पेशा अपना आदर्श खोता जा रहा है। पत्रकारिता पर व्यावसायिकता और अन्य चीजें हावी होती जा रही है। हालत यह हो गई है कि ताजा घटनाक्रमों को सही तरीके से जानने के लिए लोगों को कम से कम चार पांच बड़े अखबार पढ़ने पड़ते हैं। टीवी चैनलों के साथ भी ऐसा ही है।

- उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इससे लोगों तक खबरें सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहीं । उन्होंने कहा कि आज के दौर की आधुनिक पत्रकारिता सनसनीखेज खबरें परोसने, पेड न्यूज और न्यूज तथा व्यूज के बीच घालमेल करने के चक्रव्यूह में फंस गई है। उन्होंने मीडिया संगठनों से कृषि सहित ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें व्यवस्था की खामियों को उजागर कर जवाबदेही को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- . *"स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भारत, मेरा परिचय"।*
- *"वेस्ट टू वंडर' वेस्ट से वेल्थ'*
- साथियो, मशहूर जर्मन philosopher Schopenhauer ने लिखा था- *गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर सम्पूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है, जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कहीं जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हमारी संस्कृति, हमारी परम्परा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे, भारतीय दर्शन को नीचा दिखाने के भरपूर प्रयास चल रहे थे।*
- 'गर्म हवा के जोखिम को कम करना'
- 'समय पूर्व चेतावनी, समय पूर्व कार्रवाई'

THE CORE IAS
India's First Institute Dedicated to Answer Writing
Answer Writing & Test Series for UPSC / UPPCS / BPSC & Other States
GENERAL STUDIES MODULE Targeted Current Affairs
X1, X2, X3, X4, Batches
Mode- Online/ Offline
OPTIONAL
- Philosophy
- Anthropology
- History
- Hindi Literature
- Sanskrit Literature
- Geography
- Environment & Ecology
- Ethics With Case Studies
- Essay
- CSAT (Sure Qualifying)
- Social Issue
- Economics
- Governance
- NCERT +
Prelim - Cum - Mains
The Hindi Analysis (Editional)
Practice 1000+ MCQs in the class
Medium- Hindi/ English
8800141518 | 7827209963
Class:- A 40-41, 2nd Floor Ansal Building Mukherjee Nagar Delhi-110009
Office. : Chamber No. 3, IInd floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

THE CORE IAS

INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

CIVIL SERVICE EXAM.(PRELIMS)2019

TEST ID (NUMBER) -P1901

Time Allowed : Two Hours *Maximum Marks : 200*

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES ***NOT*** HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS, ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. **Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number and Test Booklet Series Code A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/discrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.**
3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the Box provided alongside. ***DO NOT*** write ***anything else*** on the Test Booklet.
4. This Test Booklet contains **100** items (questions). Each item is printed both in **Hindi** and **English**. Each item comprises four responses (answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose ***ONLY ONE*** response for each item.
5. You have to mark all your responses ***ONLY*** on the separate Answer Sheet provided. See directions in the Answer Sheet.
6. ***All*** items carry equal marks.
7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the response to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.
8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator ***only the Answer Sheet***. You are permitted to take away with you the Test Booklet.
9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
10. **Penalty for wrong answers :**

    THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

    (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one-third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

    (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.

    (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर छपा है ।

1. **निम्नलिखित में से कौन सा/ से विचार भारत में धर्म-निरपेक्षता के विचार से संबंधित है/ हैं?**
    1. नागरिकता की समानता और गैर-भेदभाव
    2. पर्सनल लॉ समेत अन्य धार्मिक मुद्दों में राज्य का अ-हस्तक्षेप
    3. धार्मिक विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता
    4. 10वीं कक्षा तथा समकक्ष तक शैक्षिक संस्थानों में समान और अबाध पहुँच

    नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

    a) 1,2 और 3
    b) 1 और 3
    c) 2, 3 और 4
    d) केवल 1

2. **भारत की सामाजिक व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तनों में से किसके निहितार्थ भारतीय लोकतंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण हैं?**
    1. भारत की निचली जातियों और अल्पसंख्यकों में बढ़ती राजनीतिक लामबंदी
    2. साक्षरता दर में वृद्धि
    3. भारतीय मतदाता की जनसंपर्क साधनों (मास मीडिया) तक पहुँच में व्यापक प्रसार

    नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

    a) 1,2 और 3
    b) केवल 1 और 2
    c) केवल 2 और 3
    d) केवल 1

3. **भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:**
    1. मूल-अधिकार
    2. मूल कर्तव्य
    3. राज्य के नीति-निदेशक तत्व

    भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा/ से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) द्वारा पूरे किये जा रहे हैं अथवा समर्थित है/ हैं?

    a) केवल 1
    b) केवल 3
    c) केवल 1 और 3
    d) 1,2 और 3

4. **भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
    1. इसमें प्रावधान किया गया कि भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाये गए किसी भी कानून को भारत परिवर्तित कर सकता है, जिसमें स्वयं भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 भी शामिल है।
    2. इस अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।

    उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से **सही** है/ हैं?

    a) केवल 1
    b) केवल 2
    c) 1 और 2 दोनों
    d) न तो 1 और न ही 2

5. **निम्नलिखित में से किस ने कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें युद्ध-मंत्रिमंडल सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा रखे जाने थे?**
    a) साइमन आयोग

THE CORE IAS

b) शिमला सम्मेलन

c) क्रिप्स प्रस्ताव

d) कैबिनेट मिशन

6. निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दें:

	भारी धातु	रोग
1.	मिनामाता	पारा (मर्करी)
2.	इटाई-इटाई	कैडमियम
3.	ब्लैकफुट रोग	आर्सेनिक

उपरोक्त युग्मों में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/ हैं?

a) केवल 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3

d) उपरोक्त सभी

7. भारत, रूस से S-400 खरीदने अथवा प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. S-400 वायु प्रतिरक्षा मिसाईल प्रणाली (एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम) 400 किमी तक की रेंज में आने वाले शत्रु विमान, मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है।
2. यह हवा में तैनात की जा सकने वाली लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है।

उपरोक्त में से कौन-सा/ से कथन सत्य है/ हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

8. कैटरिन प्रयोग हाल ही में ख़बरों में था। इसका सबंध है:

a) गुरुत्वीय तरंगों की खोज से

b) न्यूट्रिनो के द्रव्यमान मापन से

c) ब्रह्माण्ड के विस्तार के प्रमाण की खोज हेतु

d) इनमें से कोई नहीं

9. हाल ही में तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंसेज-जीएसपी) ख़बरों में थी। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) एक तरजीही टैरिफ प्रणाली है, जो विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को दी जाती है।
2. जीएसपी का उद्देश्य विकसित देशों में सस्ती दर पर आयात को बढ़ावा देकर गरीब देशों के विकास में सहायता करना है।
3. जीएसपी इन देशों को अपने व्यापार को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने में मदद करके लाभार्थी देशों में सतत विकास को बढ़ावा देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं ?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 2 और 3

c) 1,2 और 3

d) केवल 3

10. **निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**:

1. महिलाओं के सरंक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत लिवइन-संबंध में रहने वाली महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया गया है, क्योंकि एक पुरुष के साथ विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध

THE CORE IAS

में रहने वाली महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज नहीं कर सकती हैं।

2. घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत केवल पीड़ित द्वारा ही दर्ज की जा सकती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

11. निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल है/ हैं?

1. मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध।
2. औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और अन्य दवाओं के सेवन का निषेध ।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद दो माह की समाप्ति पर यह अप्रभावी हो जायेगा, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदन इसे संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर देते।
2. अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो यह भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर संघ से संबंधित कार्यालयों में सेवारत सभी अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु सक्षम हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

13. निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों का कार्य नहीं है:

a) जनमत तैयार करना।
b) चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना।
c) सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना
d) चुनावों में प्रवेश करके राजनीतिक शक्ति हासिल करना

14. निर्वाचित/ नामित सदस्यों के मामले में राज्यसभा सदस्यों के पद का कार्यकाल शुरू होता है:

1. आधिकारिक राजपत्र में भारत सरकार द्वारा उनके नाम अधिसूचित किए जाने की तारीख से द्विवार्षिक
2. एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए व्यक्तियों के चुनाव की घोषणा की आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

THE CORE IAS

15. आर्थिक और सामाजिक योजना एक विषय है, जिस पर:

a) केवल संसद ही कानून बना सकती है।
b) केवल राज्य विधानसभा ही कानून बना सकती है।
c) संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं।
d) संकल्पों के माध्यम से राज्य विधानसभाओं की सहमति से संसद कानून बना सकती है।

16. राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नीति केवल पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन को मान्यता देती है।
2. इस नीति में गन्ने के रस, चुकंदर जैसी चीनी युक्त सामग्री, गेहूं, टूटे हुए चावल, सड़े हुए आलू जैसे मानव उपभोग हेतु अयोग्य पदार्थों के उपयोग की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

17. गुलबर्गा की जामा मस्जिद के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मस्जिद की विशिष्टता यह है कि इसमें कोई खुला प्रांगण नहीं है और पूरी संरचना छत से ढकी हुई है।
2. इसकी शैली न तो फारसी है और न ही भारतीय है, लेकिन दोनों को सम्मिश्रण किया गया है, ताकि दोनों स्वतंत्र रूप से पहचानी न जा सकें।
3. **इसका निर्माण मोहम्मद शाह प्रथम (1358-75) ने गुलबर्गा को बहमनी सल्तनत की राजधानी बनाये जाने की स्मृति के रूप में किया था।**

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

18. खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधन पर समझौता (PGFRA) अथवा बीज समझौता किसके द्वारा लागू किया जाता है?

a) जैव विविधता पर अभिसमय
b) खाद्य एवं कृषि संगठन
c) संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन
d) अंकटाड (UNCTAD)

19. **एक प्रजाति जो यूकेलिप्टस के पत्तों को खाती है और अपनी असाधारण पैतृक-देखभाल के लिए भी जानी जाती है। उक्त प्रजाति है:**

a) कंगारू
b) कोआला
c) पेंग्विन
d) रेड कोरल स्नेक

20. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की पहल है:

1. ईट राइट मूवमेंट (सही खाना खाओ आंदोलन)
2. सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य
3. स्वस्थ भारत यात्रा
4. मोबिलाइज़ योर सिटी

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1 और 3
b) 1, 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) उपरोक्त सभी

THE CORE IAS

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य द्वारा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को भारतीय संविधान के 76 वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया।
2. सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है।
3. शिक्षा को भारत के संविधान में 42 वें संशोधन, 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) 1, 2 और 3
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) केवल 1 और 3

22. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे?

a) भीमराव अंबेडकर
b) जे.बी.कृपलानी
c) जवाहर लाल नेहरू
d) अल्लादीकृष्ण स्वामी अय्यर

23. राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवधारणा को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही नहीं हैं?

a) यह सर्वहारा वर्ग के वर्चस्व की विशेषता वाले राज्य को दर्शाता है, जो एक हिंसक क्रांति द्वारा पूंजीवादी ढांचे को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आता है।
b) यह अंतिम चरण है, जिसमें राज्य के निस्तेज हो जाने अथवा कमज़ोर हो जाने की स्थिति होती है।
c) राज्य का तंत्र लोकतांत्रिक है क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग द्वारा शासित है और यह बलपूर्वक लागू नहीं होता है।
d) यह वह चरण है, जहां 'उत्पादन के प्रमुख साधनों का पूर्ण सामाजीकरण' होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) 1, 2 और 3
b) 1 और 4
c) 2 और 3
d) 2, 3 और 4

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।
2. संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है।
3. अनुच्छेद 300 A को केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1,2 और 3

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

भारत शासन अधिनियम, 1935 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

1. प्रान्तों में द्वैध शासन का अंत
2. विधायिका की कार्यवाही पर वीटो तथा स्वयं कानून निर्माण की गवर्नर की शक्ति
3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उन्मूलन

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

THE CORE IAS

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1,2 और 3

26. एशिया में 'ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी पर कार्यशाला' (वर्कशॉप ऑन ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्री) किसकी पहल है:

a) भारत सरकार
b) आई.पी.सी.सी (IPCC)
c) जापान सरकार
d) यू.एन.एफ.सी.सी.सी. (UNFCCC)

27. हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ (NBWL) ने केंद्र के लुप्तप्राय प्रजातियों के रिकवरी कार्यक्रम में चार प्रजातियों को जोड़ा है। प्रजातियों के रिकवरी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पहल 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और केवल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है।
2. चार प्रजातियों को जोड़ने के बाद इस कार्यक्रम में कुल 17 प्रजातियां शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

28. गंगा वृक्षारोपण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की एक पहल है, जिसे 7 राज्यों में लागू किया गया है।
2. यह अभियान को नमामि गंगे कार्यक्रम के गंगा (एफआईजी) से जुड़े वनीकरण घटक के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

29. हाल ही में 'वॉलिशन एवोल्युशन' ख़बरों में था। यह सम्बद्ध है:

a) यह एक ऐसे जीव की शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन है, जो उसके आनुवंशिक ढाँचे में जानबूझकर किये गए मानवीय हस्तक्षेप के कारण होता है।
b) यह जानबूझकर मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण की विशेषताओं में परिवर्तन है।
c) यह मंगल ग्रह के वायुमंडल में परिवर्तन है, ताकि इसे जीवन योग्य बनाया जा सके।
d) यह पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन तथा इसके परिणामस्वरूप ओजोन परत पर प्रभाव से संबंधित है।

30. गुरुत्वीय रेडशिफ्ट किससे संबंधित है:

a) न्यूट्रिनो
b) बोसॉन
c) प्रोटॉन
d) प्रकाश

31. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार क्या था :

a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
b) भारत शासन अधिनियम, 1919
c) भारत शासन अधिनियम, 1935
d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

THE CORE IAS

32. भारत के संविधान के संदर्भ में, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है?

a) वन: समवर्ती सूची

b) स्टॉक एक्सचेंज: समवर्ती सूची

c) डाकघर बचत बैंक: संघ सूची

d) सार्वजनिक स्वास्थ्य: राज्य सूची

33. भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस्में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बाधित न हो?

a) अनुच्छेद 257

b) अनुच्छेद 258

c) अनुच्छेद 355

d) अनुच्छेद 356

34. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है?

a) उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश

b) उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश

c) केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

d) केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

35. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिमचंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगाली में की थी।

b) शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र, 22 मार्च को सामान्य रूप से और लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है।

c) भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

d) रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में रचित गीत 'जन गण मन' के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

36. हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हड़प्पा से जुडी वस्तुएं अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों में पाई गयी हैं।
2. हड़प्पावासी मछली सहित पौधों और जानवरों से जुड़े कई उत्पादों का सेवन करते थे।
3. अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध-शुष्क और उप-आर्द्र भूमि में स्थित हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

a) 1 और 3

b) 1,2 और 3

c) 1 और 2

d) उपरोक्त सभी

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सातवाहन जिन्होंने पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, उन्होंने लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व प्राप्त किया।
2. सातवाहन राजाओं में सबसे प्रसिद्द सातकर्णी-प्रथम था और यह प्रसिद्धि सभी दिशाओं में उसकी सैन्य विस्तार की नीति के कारण थी।
3. सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था सामंती थी। उन्होंने कई सामंती प्रमुखों के बीच अपने साम्राज्य को विभाजित किया था, जो भू राजस्व प्रणाली का प्रबंधन करते थे और प्रशासन की देखरेख करते थे।

उपरोक्त में से कौन-सा/ से कथन सत्य है/हैं ?

a) केवल 1 और 3

THE CORE IAS

b) केवल 1

c) केवल 1 और 2

d) केवल 2 और 3

38. हरिषेण किसका दरबारी कवि था?

a) चंद्रगुप्त

b) समुद्रगुप्त

c) अशोक

d) सेनगुत्तुवन

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बुद्ध के उपदेशों में से कोई भी उनके जीवनकाल में लिखा नहीं गया था।
2. बुद्ध के उपदेशों के संकलन को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है अर्थात विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए तीन टोकरी। उन्हें पहले मौखिक रूप से प्रेषित किया गया था और फिर लंबाई तथा विषय के अनुसार लिखा और वर्गीकृत किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

40. "यद्यपि बुद्धिमानों को लगता है कि इस पुण्य से ... इस तपस्या से उसे कर्म की प्राप्ति होगी ... और मूर्ख को अपने कर्मों से धीरे-धीरे छुटकारा पाने की आशा रहती है,किन्तु दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सुख और दुःख को संसार में नहीं टाला जा सकता है। इसे न तो कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है ...जैसा कि किसी धागे के गुच्छे को उसकी पूर्ण लम्बाई तक खोल दिया जाता है। उसी प्रकार मूर्ख और बुद्दिमान दोनों ही अपने दुःख का अंत कर सकेंगे" । यह शिक्षा है:

a) महावीर

b) पार्श्वनाथ

c) बुद्ध

d) नानक देव

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

भारत में, वित्तीय लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क :

1. राज्य सरकार द्वारा आरोपित और एकत्र किया जाता है।
2. संघ सरकार द्वारा विनियोजित होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

42. नागरिकता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
2. भारत में केवल जन्म से नागरिक और प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं।
3. प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

a) 1 और 2

b) 2 और 3

c) केवल 3

d) 1 और 3

THE CORE IAS

43. निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 लागू करने का कारण बनेगी?

1. धनबल का प्रयोग
2. बाहुबल का प्रयोग
3. बूथ पर कब्ज़ा (बूथ कैप्चरिंग)

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

44. निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताएं है/ हैं?

1. वापस बुलाये जाने की प्रक्रिया (रिकॉल) का प्रयोग
2. कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है।
3. विधि का शासन
4. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) 1 और 2
b) 1,2 और 3
c) 2,3 और 4
d) 2 और 4

45. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य प्रकृति का है?

1. अस्पृश्यता का निषेध
2. मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध
3. धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।
4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) 1,2 और 3
b) 2 और 3
c) 3 और 4
d) 2,3 और 4

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जैन धर्म के अनुसार पूरा संसार चेतनाशील है, यहां तक कि पत्थरों, चट्टानों और पानी में भी जीवन है।
2. जैन धर्म के अनुसार, ब्रह्मांड और उसके घटक- आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति के सिद्धांत हमेशा मौजूद रहे हैं। सभी घटक और कार्य सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित होते हैं।
3. जैन उपदेशों के अनुसार, कर्म ही जन्म और पुनर्जन्म के चक्रका कारण है। कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्य और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसारिकता त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वैराग्यपूर्ण अस्तित्व मोक्ष प्राप्ति की एक आवश्यक शर्त है।

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) केवल 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

47. अरबी में लिखी गई रेहला नामक पुस्तक चौदहवीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बेहद समृद्ध और रोचक विवरण प्रदान करती है। इस पुस्तक के लेखक हैं:

a) अल बरुनी

THE CORE IAS

b) इब्न बतूता

c) बाबर

d) ज़ैतून

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

फारसी भाषा:

1. भारत में तुर्क-आगमन के साथ फारसी की शुरुआत हुई थी।
2. तुर्कों ने देश में साहित्य और प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी को अपनाया।
3. दिल्ली फारसी भाषा के विकास का पहला केंद्र बनकर उभरा।
4. फारसी भाषा के सबसे उल्लेखनीय लेखक अमीर खुसरू थे, जो भारत में पैदा हुए थे।

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) 1,2 और 4

b) 1,2 और 3

c) 3 और 4

d) 2 और 4

49. भारत में दार्शनिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सांख्य दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार प्रकृति और आध्यात्मिक तत्व मिलकर संसार का निर्माण करते हैं।
2. योग दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति ध्यान और शारीरिक अनुप्रयोग (व्यायाम) के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
3. वेदांत दर्शन में वैदिक कर्मकांडों पर जोर दिया गया है, जिसमें पुजारियों की आवश्यकता होती है।
4. पुनर्जन्म मीमांसा दर्शन का आवश्यक तत्व है।

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) 1,2 और 4

b) 1 और 2

c) 2 और 3

d) उपरोक्त सभी

50. भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भक्ति ने मुक्ति पाने के साधन के रूप में ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति के बजाय सही ज्ञान और कर्म पर जोर दिया है।
2. भक्ति की विशेषताओं में धार्मिक कट्टरता का त्याग, जाति के प्रति उपेक्षा और समाज के सभी वर्गोंमें समानता शामिल है।
3. गुरु नानक और कबीर भक्ति आन्दोलन के प्रसिद्ध संत थे।

उपरोक्त में से कौन-सा से कथन सही है/हैं ?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 1 और 2

c) केवल 2 और 3

d) उपरोक्त सभी

51. निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा/से राज्य, पूर्ण राज्य बनने से पहले केंद्रशासित प्रदेश था/ थे?

1. गोवा
2. हिमाचल प्रदेश
3. अरुणाचल प्रदेश

उपरोक्त में से कौन-सा/से विकल्प सही है/हैं ?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 2 और 3

d) 1,2 और 3

52. भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का अर्थ है:

THE CORE IAS

a) संविधान की कुछ विशेषताएं, इसके लिए इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है।

b) मौलिक अधिकारों का न तो हनन किया जा सकता है और न ही उनको कम किया जा सकता है।

c) अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

d) संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है और साथ ही साथ यह उसकी वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व भी करता है।

53. प्रस्तावना संवैधानिक व्याख्या में उपयोगी है, क्योंकि यह :

a) शक्ति और सीमा का एक स्रोत है।

b) संविधान की मूल विशेषताओं की विस्तृत जानकारी देती है।

c) a तथा b दोनों

d) दोनों में से कोई नहीं

54. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रदान की गई है।
2. भारत के संविधान में सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

55. भारत के संविधान द्वारा केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना इंगित करता है:

a) कि भारत एक संघीय राजव्यवस्था है

b) कि भारत न तो संघीय है और न ही एकात्मक है

c) कि भारत अर्ध संघीय है

d) भारतीय राजव्यवस्था का एकात्मक चरित्र है

56. हाल ही में मुंबई की आर्ट डेको इमारतें, जिसे मियामी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है, को शहर की प्रसिद्द विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. आर्ट डेको इमारतों में आवासीय प्रॉपर्टी, वाणिज्यिक कार्यालय, अस्पताल और सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटर शामिल हैं, जिनमें लोकप्रिय रीगल और इरोस सिनेमा भी शामिल हैं।
2. आर्ट डेको इमारतों की विशेषताओं में सुन्दर डेको फोंट, संगमरमर के फर्श और सर्पिल सीढ़ियां शामिल हैं।
3. विक्टोरियन वास्तुकला इमारतों का निर्माण धनी भारतीयों द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने अपने वास्तुकारों को औपनिवेशिक शासकों द्वारा इस्तेमाल किये गए डिजाइनों से अलग डिजाइन देखने या सीखने यूरोप भेजा था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 1 और 2

c) केवल 2 और 3

d) केवल 3

57. **अंबुबाची मेला संबंधित है**:

a) सबरीमाला

b) कामाख्या

c) तारिणी

d) शनिशिगनापुर

58. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

THE CORE IAS

1. वाकाटक वंश ने 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दक्षिण-मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उत्तर में उनके समकालीन सातवाहनों की तरह ही दक्कन में वे मजबूती से स्थापित थे। वे गुप्तों के महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी थे।
2. दक्कन के समकालीन राजवंशों के विपरीत, वाकाटक ने बौद्ध धर्म अपनाया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

59. निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक नैतिकता का पहलू है:

1. इसमें वे युक्तियाँ शामिल हैं जो किसी भी संविधान, संसद या न्यायलय में स्वीकार्य हों।
2. एक संवैधानिक नैतिकता को इस संभावना के साथ रखने की आवश्यकता है कि अंततःएक प्रक्रिया से क्या परिणाम निकलता है जो नागरिकों की परिकल्पना से अलग है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

60. निम्नलिखित में से किसे 'संविधान का विवेक' कहा गया है?

1. राज्य नीति के निदेशक तत्व
2. मौलिक अधिकार
3. मौलिक कर्तव्य

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1
d) उपरोक्त सभी

61. जनहित याचिका (पीआईएल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पीआईएल भारतीय न्यायपालिका के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
2. अनुच्छेद 32 की न्यायिक समीक्षा द्वारा भारत में जनहित याचिका की प्रणाली शुरू की गई है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

62. 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की।
2. इसने द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की।
3. इसने विधान परिषदों को पहली बार बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी।
4. परिषदों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली शुरू की गई।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1 और 2
b) 2,3 और 4
c) 3 और 4
d) 1 और 3

THE CORE IAS

63. निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 -18 के प्रावधानों के तहत समानता के अधिकार से संबंधित हैं?

1. धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
2. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
3. अल्पसंख्यकों को धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार
4. अस्पृश्यता का उन्मूलन

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) 1,2 और 3
b) 3 और 4
c) 1,2 और 4
d) 1 और 2

64. संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है?

1. प्रस्तावना
2. राज्य के नीतिनिदेशक तत्व
3. मौलिक अधिकार
4. मौलिक कर्तव्य

उपरोक्त विकल्पों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) 1 और 2
b) 1,2 और 3
c) 2,3 और 4
d) उपरोक्त सभी

65. नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नागरिकता नियम, 2003 को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाया गया था, जो नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने की विधि बताता है।
2. असम के NRC में ऐसे व्यक्ति और उनके वंशज शामिल होंगे, जिनके नाम 24 मार्च, 1971 मध्य रात्रि तक की मतदाता सूची या नागरिक रजिस्टर, 1951 में शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

66. नयनार किसके भक्त थे?

a) विष्णु
b) शिव
c) कृष्ण
d) दुर्गा

67. **लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. लिंगायतों के संस्थापक बासवन्ना थे जो प्रारंभ में एक जैन थे।
2. लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव के साथ एकाकार हो जाएगा और इस संसार में वापस नहीं आएगा।
3. लिंगायतों ने वयस्कों के विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया।
4. लिंगायतों ने जाति के विचार को चुनौती दी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 1, 3 और 4
c) केवल 2 और 4
d) उपरोक्त सभी

THE CORE IAS

68. इस्लाम में तसव्वुफ़ संबंधित है:

a) सलाफीवाद
b) सूफीवाद
c) सामीवाद
d) वहाबी

69. पुलिकली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह केरल की एक प्रसिद्ध लोक कला है जो महिला कलाकारो से संबंधित है।
2. यह ओणम से संबंधित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

70. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. भारतीय प्रणाली संसद की संप्रभुता पर आधारित है।
2. एक व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

71. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

a) उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनके पद की शपथ में भारत के संविधान और उसमें शमिल कानूनों को पालन करना शामिल है।
b) वह पद ग्रहण करने से से छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक पद पर बना रहेगा।
c) उन्हें दो तिहाई बहुमत से समर्थित संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संबोधन के बाद केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
d) उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य के अंतर्गत पद के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

72. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के आधार पर स्थापित किया गया था, जिसमें सरकार को ओबीसी सूची में जातियों को शामिल करने के तरीकों को लेकर निर्देश दिया गया था।
2. इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की शिकायतों पर स्वतःसंज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

73. 'राज्य' शब्द का उपयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, जिसके विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा दी जाती है। 'राज्य' में निम्नलिखित में से कौन शामिल हो सकता है?

1. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
2. जिला योजना समिति

THE CORE IAS

3. सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) अनुबंध के तहत एक निजी निकाय

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

74. निम्नलिखित में से कौन-सी उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत अस्वीकृत है?

1. नाइटहुड
2. भारत रत्न
3. जमींदार

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

75. **दक्कन के सातवाहन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**:

1. करीमनगर जिले के कोटालिंगला और संगारेड्डी में प्रारंभिक सातवाहन सिक्कों की खोज, पूर्वी दक्कन में उनके शासन की शुरुआत की परिकल्पना का समर्थन करती है।
2. नानेघाट और नाशिक शिलालेख पश्चिमी दक्कन में उनके शासन की शुरुआत की ओर संकेत करते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

76. **प्राचीन संस्कृत और पाली ग्रंथों में ऐसी भूमि का उल्लेख है, जिसे सुवर्णद्वीप या सुवर्णभूमि के रूप में जाना जाता है। वह है** :

a) श्रीलंका
b) दक्षिण-पूर्व एशिया
c) तिब्बत
d) हिंदुकुश का उत्तर-पश्चिम क्षेत्र

77. नागार्जुनकोंडा में मंदिर परिसरों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है?

a) अधिकांश मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था।
b) मंदिरों की दीवारें अपेक्षाकृत समतल थीं।
c) पत्थर मुख्य निर्माण सामग्री थी।
d) उनके पास एक-समान वास्तु योजना नहीं थी।

78. निम्नलिखित स्तूपों में से एक में एक नक्काशीदार पैनल है, जिसमें' अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट को दिखाया गया है, जैसा कि एक प्राकृत शिलालेख में भी उल्लिखित है ?

a) अमरावती
b) भरहूत
c) साँची
d) वैशाली

79. भारत में जनहित याचिका की प्रणाली शुरू की गई है:

a) संवैधानिक संशोधन के माध्यम से
b) न्यायिक पहल द्वारा
c) अनुच्छेद 32 की न्यायिक समीक्षा द्वारा
d) संसदीय संकल्प द्वारा

80. 'धर्मशास्त्र' में उल्लिखित स्त्री-संपत्ति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महिलाओं का स्त्री-धन' पर अधिकार था, जिसमें शादी के समय माता-पिता द्वारा दिए गए और

THE CORE IAS

अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव शामिल थे।

2. यह धन माँ द्वारा बेटी के सुपुर्द कर दिया जाता था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

81. भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:?

1. भारतीय संविधान को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था।
2. संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद भी थी।
3. संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर.अम्बेडकर थे।
4. 1950 में भारत के संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया, जिससे भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही नहीं है/ हैं?

a) 1,2 और 3
b) 1 और 4
c) 3 और 4
d) 2,3 और 4

82. हाल ही में प्रोजेक्ट रामा (RAMA) ख़बरों में था, यह संबंधित है:

a) नासा
b) इसरो
c) जाक्सा (JAXA)
d) यूरोपियन स्पेस एजेंसी

83. भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (BCSBI)के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे फरवरी 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं हेतु बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में स्थापित किया गया था।
2. यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। BCSBI की सदस्यता स्वैच्छिक है और अनुसूचित बैंकों के लिए खुली है। प्रारंभ में BCSBI की सदस्यता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए खुली थी और अब इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

84. राष्ट्रीय पोषण मिशन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समग्र पोषण के लिए एक व्यापक योजना है, जो बौनेपन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों से जुड़े मामलों को कम करने का प्रयास करती है।
2. इसे जन आन्दोलन बनाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना पोषण अभियान के घटकों में शामिल है।
3. भारत सरकार द्वारा इस योजना का 60% वित्तपोषण और विश्व बैंक या अन्य बहुराष्ट्रीय

THE CORE IAS

विकास बैंकों द्वारा 40% वित्त पोषण किया जाएगा।

4. वर्तमान में यह पूरे भारत में लागू है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) 1,3 और 4
b) 1 और 2
c) 1 और 4
d) उपरोक्त सभी

85. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 1995 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं की औपचारिक रूप से देखरेख करने के उद्द्देश्य से स्थापित केंद्र सरकार का कार्यकारी निकाय है।
2. एनसीटीई ने पूरे देश में (केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए) शिक्षकों की शिक्षा के लिए प्रणाली के विकास की योजना बनाई है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

86. रानी की वाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, 900 साल पुरानी संरचना है। यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और 2016 में भारत में सबसे स्वच्छ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मानित किया गया था। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है।
2. इसका निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने 11 वीं शताब्दी में अपने मृत पति भीमदेव प्रथम के स्मारक के रूप में करवाया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

87. 'ऋग्वेद' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. न केवल दसा बल्कि आर्य शत्रुओं को पराजित करने के लिए इंद्र से याचना इस और इंगित करती है, कि आर्यों के बीच में संघर्ष थे।
2. 'ऋग्वेद' में राजन शब्द को राजा के बजाय एक मुखिया अथवा प्रधान के रूप में उल्लिखित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

88. चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आदर्श आचार संहिता भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई है।
2. आदर्श आचार संहिता, 1968 में राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी अभियान के कुछ मानदंडों का पालन करने के लिए एक स्वैच्छिक निर्णय के रूप में उभरी।
3. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है।

THE CORE IAS

4. भारत के चुनाव आयोग के पास चुनाव की तारीखों की घोषणा के दिन से आदर्श आचार संहिता लागू करके चुनावी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने की शक्ति है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही नहीं है/ हैं?

a) 1 और 3
b) केवल 1
c) 3 और 4
d) 2 और 4

89. भारत में विशेष श्रेणी के राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं।
2. ये सीमावर्ती राज्य हैं।
3. ये अपेक्षाकृत अविकसित हैं।
4. ये तटीय राज्य हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) 1 और 2
b) 1,3 और 4
c) 2 और 3
d) 1,2 और 3

90. अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) राजा के रूप में उसके राज्याभिषेक के बाद शिलाओं और स्तंभों पर खुदाई करके लेख लिखने की प्रथा शुरू हुई।
b) अच्छे आचरण और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए कोई संदर्भ अभिलेखों में मौजूद नहीं है।
c) अभिलेखों में उल्लिखित है कि लोगों द्वारा आयोजित किए गए सभी समारोहों को राजा द्वारा समर्थन दिया जाता था।
d) उनमें आशा व्यक्त की गयी है कि लोग स्वयं के अलावा अन्य संप्रदायों की आलोचना करने में संयम बरतेंगे।

91. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए 'मौलिक अधिकारों' के बारे में सही है?

1. संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार एक मौलिक अधिकार है।
2. संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत सभी कानूनों को शून्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होता है।
3. सुरक्षा का अधिकार, 'अपराधों की सजा के संबंध में, यह दावा करता है कि अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
4. राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत को प्रभावी करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है।

नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) 1,2,3 और 4
b) 1 और 2
c) 3 और 4
d) 2,3 और 4

92. भारतीय शिल्प और विरासत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हिंदू जाति व्यवस्था की स्थिर प्रकृति ने कई शिल्प रूपों को जीवित रखा है।

THE CORE IAS

2. पूर्व-मुगल राजा ज़ैन-उल-अबीदिन द्वारा कालीनों और शॉल के बेहतर रूपों को बुनने का कौशल कश्मीर में लाया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

93. एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाये गए हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर हैं।
2. वे 6 वीं से 15 वीं शताब्दी के बीच चट्टानों पर उकेरे गए थे। इसका सबसे शानदार उदाहरण 8वीं शताब्दी में बना कैलाश मंदिर है, जो 32 मीटर ऊंचा है तथा चट्टानों को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

94. बिदरी धातु शिल्प, एक तकनीक को संदर्भित करता है:

a) यह तिरुवनंतपुरम में किया जाने वाला सोने और चंडी से जुड़ा काम है।
b) चांदी से जुड़ी पच्चीकारी, जिसमें जस्ता,तांबा और सीसा की नरम मिश्र धातु का भी इस्तेमाल होता है, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
c) यह चौड़े मुंह वाला खाना पकाने वाला बर्तन है, जिसमें सपाट या घुमावदार रिम होते हैं।
d) इनमें से कोई नही।

95. पारंपरिक कढ़ाई जिसे फुलकारी कहा जाता है, कहाँ से संबंधित है:

a) उत्तर प्रदेश
b) पंजाब
c) राजस्थान
d) केरल

96. गांधार कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियाँ ग्रीक-रोमन शैली में बनायीं गयी हैं।
2. ग्रीक-रोमन शैली में बुद्ध के बाल संवारे नहीं गए हैं।
3. गांधार कला का विस्तार मथुरा में हुआ और इसके अनुसार महावीर की कई मूर्तियों का निर्माण किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) 1,2 और 3

97. भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक स्तंभ रहित हॉल को मण्डप कहा जाता था।
2. दक्षिण में मंदिर वास्तुकला ने चोलों के अधीन अपना चरम प्राप्त किया।
3. .चोल-वास्तुकला की शैली को द्रविड़ वास्तुकला भी कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) केवल 3

THE CORE IAS

98. टॉमस रो और विलियम हॉकिन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत थे।
2. वे अकबर के दरबार में आये थे।
3. वे ईसाई मिशनरी थे और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2
d) केवल 3

99. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. श्रवणबेलगोला अपनी जैन विरासत और इतिहास के लिए प्रसिद्द है।
2. अजंता जैन मूर्तियों और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
3. मामल्लपुरम एकाश्म चट्टानों को काटकर बने बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्द है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2
d) 2 और 3

100. अशोक के प्रशासन का महत्व इसमें निहित है:

a) अशोक के स्तंभलेखों तथा शिलालेखों में।
b) भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार में।
c) धम्म की अवधारणा के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी के विचार को प्रभावित करना।
d) बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाने के उसके प्रयास।

THE CORE IAS

THE CORE IAS
INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

CIVIL SERVICE EXAM. (PRELIMS) 2019

TEST ID (NUMBER) -P1901

समय : दो घण्टे *पूर्णांक : 200*

अनुदेश

1. **परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश, आदि न हो । यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिए ।**
2. **कृपया ध्यान रखें कि OMR उत्तर-पत्रक में, उचित स्थान पर, रोल नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम A, B, C या D को, ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है । किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा ।**
3. इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है । परीक्षण पुस्तिका पर ***और कुछ न*** लिखें ।
4. इस परीक्षण पुस्तिका में **100** प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं । प्रत्येक प्रश्नांश **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपा है । प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं । इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं । यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे । प्रत्येक प्रश्नांश के लिए ***केवल एक ही*** प्रत्युत्तर चुनना है ।
5. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ***ही*** अंकित करने हैं । उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखिए ।
6. ***सभी*** प्रश्नांशों के अंक समान हैं ।
7. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं ।
8. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर ***केवल उत्तर-पत्रक*** अधीक्षक को सौंप दें । आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है ।
9. कच्चे काम के लिए पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न हैं ।
10. **ग़लत उत्तरों के लिए दंड :**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए ग़लत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा ।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं । उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक ग़लत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का **एक-तिहाई** दंड के रूप में काटा जाएगा ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **ग़लत उत्तर** माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही, उसी तरह का दंड दिया जाएगा ।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा ।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

Note : English version of the instructions is printed on the back cover of this Booklet.